स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–19, अंक–5, वैशाख–ज्येष्ठ 2068, मई 2011

संपादक
विक्रम उपाध्याय

कार्यालय
धर्मक्षेत्रा, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी
दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

आवरण कथा-4

माया‌वती हो या सोनिया गांधी मौखिक रूप से सबकी प्राथमिकता किसान हैं। फिर भी किसान बर्बाद हो रहे हैं। यह कम दुखद नहीं है कि 100 करोड किसानों के रहते हुए उनके पास सिर्फ 27 फीसदी भूमि का मालिकाना हक रह गया है। शेष सभी भूमि मोटे साहुकारों या निजी कंपनियों के हाथ चली गई हैं। क्या होगा इस देश का।

अनुक्रम

आवरण लेख : जोर जबर्दस्ती से अधिग्रहण
पहले जमीन गई अब जान भी जा रही है
– विक्रम उपाध्याय /4

आंदोलन
राष्ट्रीय परिषद् बैठक में पारित प्रस्ताव /7

कृषि
खेती पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की निगाहें
– भारत डोगरा /10

पलायन
गांव से शहर की ओर पलायन के कारण एवं निवारण
– डॉ. नन्द सिंह नरूका /12

मुद्दा
बढ़ती आबादी, बढ़ता खाद्य संकट
– जयंतीलाल भंडारी /15

प्रतिक्रिया
शून्य सहनशीलता का सच
– बलवीर पुंज /17

सामयिकी : लड़ाई का अगला मोर्चा
– ब्रह्मा चेलानी /19

तर्क–वितर्क : आज भी नहीं मिल पाया है श्रमिकों को सम्मान
– बजरंग मुनि /22

सवाल : आम आदमी पर कर का बोझ
क्रिकेट और कारपोरेट को दी जाती है भारी कर रियायतें
– डॉ. कृष्णस्वरूप आनन्दी /26

संस्कृति : सामाजिक मूल्यों का पतन और स्वदेशी
– विश्वतोष श्रीवास्तव /28

लेख : भ्रष्टाचार हिंसा, सदाचार अहिंसा है
– राजेन्द्र सिंह /29

एक नज़र : भ्रष्टाचार के बाद देश
– डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल /32

दृष्टिकोण :
जैतापुर : आणविक ऊर्जा के विरोध में उठती आवाज
– डॉ. अश्विनी महाजन /35

पाठकनामा /2

पाठकनामा

जन एकता न बनने के कारण फैलता है रिश्वत

अक्सर मैं स्वदेशी पत्रिका पढ़ता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि देश की सारी समस्याएं हमारे द्वारा ही पैदा की गई हैं। हमारा देश भ्रष्टाचार के दलदल में आकंठ डूबा हुआ है। कोई भी सरकारी काम रिश्वत दिए बगैर हो ही नहीं सकता। ईमानदार आदकी को सरकारी विभाग के इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं कि वह भी हार मान लेता है। इस रिश्वत की संस्कृति पर हमला करने की जरूरत है। सरकारी कार्यालयों में रिश्वत देने के बजाय धरना व प्रदर्शन करना चाहिए ताकि रिश्वत लेने वाले कर्मचारी को अपनी नौकरी जाने का भय रहे। रिश्वत लेने वाले को तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाए और उसकी पेंशन इत्यादि न दी जाए ।

– अमरेश कुमार, आया नगर, नई दिल्ली

अन्ना के बाद बाबा रामदेव

अन्ना हजारे के आमरण अनशन की हवा सरकार ने निकाल दी। लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जैसे ही लामबंद हुए, सरकार और कांग्रेस के नुमाइंदों ने एक कमेटी बनाने की औपचारिक घोषणा कर अन्ना की अनशन तुड़वा दी। बाद में इन्हीं लोगों ने अन्ना के लोगों को बदनाम करने की साजिश रच कर आंदोलन को पटरी से उतार दिया। अब बाबा रामदेव अनशन करने जा रहे हैं। बिना लोक दबाव के सरकार झुकेगी नहीं और भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। लेकिन इस बात की सावधानी बरतनी होगी कि कहीं अन्ना की तरह बाबा रामदेव को भी सरकार बदनाम करने की मुहिम न शुरू कर दे। इसके पहले दिग्विजय सिह इस योगगुरु की संपत्ति को लेकर जनता में आशंका फैलाने की कोशिश कर चुके है। मेरी बाबा से प्रार्थना है कि इस बार बिना किसी निष्कर्ष के आंदोलन स्थगित न करे। भ्रष्टाचार का मुद्दा किसी एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं है। इससे पूरा देश प्रभावित है। हर आदमी त्रस्त है। इससे भारत को मुक्ति मिलनी ही चाहिए।

– आयुषी उपाध्याय, गाजियाबाद

दो पंक्तियां

मेरी रगो में खून, देश के लिए है
सींच दो इससे नई पीढ़ी के सपने को
कर्म पथ पर बढ़ते रहे और जीए सिर उठाकर
करे काम न ऐसा कोई जग के उस पर हसने को

– राजीव, दिल्ली

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

"धर्मक्षेत्र" शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 100 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्क: 1,000 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

(ध्यानार्थ : कृपया अपना नाम व पता साफ अक्षरों में लिखें)

उन्होंने कहा

ओसामा हजारों निर्दोषों की हत्या का दोषी था। उसके मारे जाने भर से ही अमेरिका का अभियान खत्म नहीं हुआ। हम एक बार फिर याद दिला दें कि अमेरिका जो ठान लें वह करके दिखाता है।

– बराक ओबामा

पाकिस्तान का यह बहाना अब नहीं चलेगा कि उसे लादेन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। यह समय चुप रहने के बजाए बोलने का है। अब पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कर देना चाहिए।

– सलमान रूशदी

मुंबई आतंकी हमला अमेरिका पर हुए 9/11 हमले से कम नहीं है। भारतीयों की जान अमेरिकियों से कम नहीं है। हमें भी उसी तरह अपने दुश्मनों पर कार्रवाई का अधिकार है।

– यशवंत सिन्हा

संपादकीय

करे सरकार भरे जनता

महंगाई के मुद्दे पर सरकार के विफल होने के बाद रिजर्व बैंक के उपर ही यह जिम्मेदारी आती है कि वह अपने तरीके से महंगाई के आकड़े कम करे। पिछले हफ्ते घोषित मौद्रिक नीति में रिजर्व बैंक ने एक बार फिर कर्ज महंगा करने और मांग को नीचे लाने का फैसला किया। रेपो रेट में आधा फीसदी बढ़ोतरी का मतलब ही यह है कि बैंकों को अब रिजर्व बैंक से ऊंची दर पर पैसा मिलेगा और बैंक अब महंगी दर पर उपभोक्ताओं या व्यावसायियों को कर्ज देंगे। यानी अब उद्योग धंधों को मुश्किल हो जाएगी अपने लिए पैसे जुटाने में। साथ ही आम उपभोक्ता जो अपनी जरूरतों के लिए कर्ज लेता है, उसे भी मायूस बैठना पड़ेगा। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने रिजर्व बैंक के इस कदम को जायज ठहराते हुए यह कहा है कि तेजी से बढ़ रही मुद्रा स्फीति की दर को कम करने के लिए यही उपाय था। यानी सरकार मान रही है कि उसके पास महंगाई कम करने का कोई रास्ता नहीं बचा है। सरकार की अपनी विफलता का खामियाजा आम आदमी या उद्योग भुगते। अब घर खरीदना महंगा, कार खरीदना महंगा और धधा चलाना भी मुश्किल। अब लोग यह मानने लगे हैं कि रिजर्व बैंक के इस कदम से कर्ज की दर दहाई अंक में पहुंच जाएगी। अब यह सरकार ही निश्चित करें कि इतनी महंगी अर्थव्यवस्था को लेकर किस तरह से 2020 तक आर्थिक सुपर पॉवर बनने का सपना देख रही है। आज भी अमरीका, जापान या अन्य विकसित देशों में कर्ज पर ब्याज दर पांच फीसदी से अधिक नहीं है। अर्थात् उधोग धंधे या व्यापार के लिए आज भी वे देश बड़े निवेशकों के लिए प्राथमिकता वाले देश होंगे। भारत ने इस मामले में अपनी बढ़त खो दी है। ज्यादा दूर क्यों जाए चीन का ही उदाहरण लें। आसानी से वित्त उपलब्ध होने और अनुकूल नियम कानून होने के कारण ही भारत की कंपनियां यहां से चीन जाने लगी है। तमाम बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने यहां से डेरा–डंडा उठाकर चीन में जमा लिया है। चीन यूं ही दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश नहीं बन गया है लेकिन हमारे यहां तो सरकार महंगाई के मुद्दे से ही नहीं लड़ पा रही है। लगातार पांच वर्षों से महंगाई बढ़ रही है और सरकार एक ही बात कहती है कि उसके पास जादू की छड़ी नहीं है। बहरहाल नई मौद्रिक नीति न सिर्फ कर्जे को महंगा करेगी बल्कि विकास को भी अवरूद्ध करेगी। आवासीय ऋण महंगे होने से सिर्फ रियल एस्टेट कारोबार ही नहीं बैठेगा बल्कि इस्पात, सीमेंट और इससे जुड़े अन्य उद्योग धंधे भी चौपट होंगे। सबसे बड़ी समस्या मजदूरों की आएगी, क्योंकि रियल एस्टेट क्षेत्र में इन दिनों सबसे अधिक रोजगार मिल रहा है। देश की औद्योगिक विकास दर पर भी असर पड़ेगा। इस समय ढांचागत क्षेत्र में कई परियोजनाएं चल रही हैं। यदि उन्हें समय पर वित्तीय साधन उपयुक्त दर पर नहीं मिला तो ये सारी योजनाएं ठप्प पड़ सकती है और कहने की आवश्यकता नहीं है कि इनकी लागत में हजारों करोड़ों रूपयों की वृद्धि हो सकती है। रिजर्व बैंक की यह दलील है कि कर्ज महंगे करने से चीजों की मांग कम हो जाएगी और मांग कम होने से कीमत अपने आप नीचे आ जाएगी। रिजर्व बैंक भी जानता है कि रेपो रेट में वृद्धि कोई दीर्घकालीन उपाय नहीं है। बल्कि यह बैंकिंग उद्योग के लिए प्रतिकूल ही है क्योंकि कर्ज पर ब्याज की दरें बढ़ाने के साथ–साथ जमा पर भी ब्याज दरें बढ़ाने पड़ेगी जो बैंक के लिए एक तरह से देनदारी है। बैंकिंग उद्योग के लिए कभी भी यह लाभदायक स्थिति नहीं होती। बैंक कम दर पर पैसा उठाकर उद्योग को वित्त पोषण करता है तो उसे लाभ होता है। इसके विपरीत वह अधिक ब्याज दर पर पैसा उठाकर और कर्ज कम जारी कर, नुकसान में होता है। हालांकि यह मौद्रिक नीति सिर्फ तीन महीने के लिए है आने वाले अगले तीन महीनों में अगर स्थिति सुधरती है। तो वापस कर्ज सस्ता हो सकता है लेकिन यह जिम्मेदारी सरकार पर होती है कि वह महंगाई पर काबू पाए और लोगों की आय बढ़ाने में सहायता करें और उद्योग धंधों के लिए उचित माहौल बनाए। फिलहाल यह रास्ता कठिन नजर आता है।

जोर जबर्दस्ती से अधिग्रहण

पहले जमीन गई अब जान भी जा रही है

दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में किसानों ने अपनी जमीन के अधिग्रहण की कीमत सिर्फ 200 रुपये प्रति वर्ग गज बढ़ाने के लिए आंदोलन किया। जब शासन ने नहीं सुनी तो आंदोलन किया। आंदोलन से बात नहीं बनी तो सरकारी कर्मचारियों को बंधक बनाया तब भी सरकार के कान पर जू नहीं रेंगा। नतीजा ग्रामीणों और पुलिस के बीच भिड़ंत हुई तीन पुलिस वाले मारे गए। जिलाधिकारी को गोली लगी। 15 किसान मरणासन्न स्थिति में अस्पताल में पड़े हैं।

■ विक्रम उपाध्याय

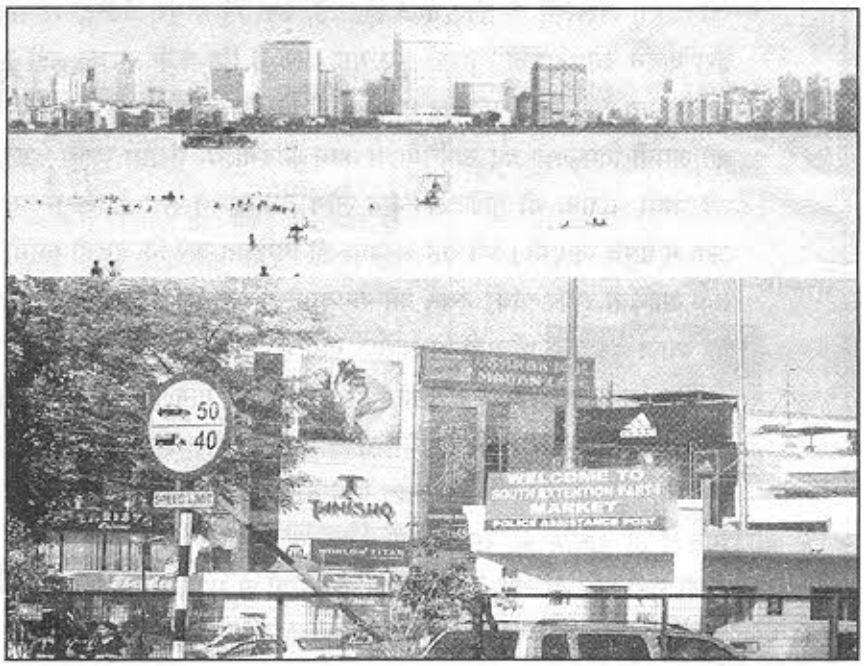

देश एक स्वरूप दो। और दोनों एक दूसरे के एक दम विपरीत कैसे तो ये खबर पढ़िए।

मुंबई में एक 3000 वर्ग फीट का फ्लैट 20 करोड़ में बिका है। तीन कमरों के इस फ्लैट की इतनी बड़ी कीमत इस लिए लगाई है, क्योंकि इससे समुद्र दिखता है। इसमें सभी सुख सुविधाएं हैं और इसके मालिक के पास इतनी बड़ी रकम है कि वह 20 करोड़ सिर्फ एक फ्लैट खरीदने के लिए खर्च कर सकता है। एक और खबर दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक 600 वर्ग गज का भूखंड 61.5 करोड़ में बिका है। इस पर जो फ्लैट बनेंगे उनमें से किसी की भी कीमत 20 करोड़ रुपये से कम नहीं होगी।

मुंबई में एक 3000 वर्ग फीट का फ्लैट 20 करोड़ में बिका है। तीन कमरों के इस फ्लैट की इतनी बड़ी कीमत इस लिए लगाई है, क्योंकि इससे समुद्र दिखता है. . .एक और खबर दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक 600 वर्ग गज का भूखंड 61.5 करोड़ में बिका है. . ... .यह उस भारत की तस्वीर है जहां विलासिता के लिए पैसे खर्च ने की कोई सीमा नहीं है।

क्या इतने पैसे में घर खरीदने वाले लोग हैं। बिल्डर का जवाब है अभी बनना शुरू नहीं हुआ और हमने द्वितीय तल [illegible]50 करोड़ में बेच दिया है। यह उस भारत की तस्वीर है जहां विलासिता के लिए पैसे खर्च ने की कोई सीमा नहीं है। अब एक और भारत देखिए : दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में किसानों ने अपनी जमीन के अधिग्रहण की कीमत सिर्फ 200 रुपये प्रति वर्ग गज बढ़ाने के लिए आंदोलन किया। जब शासन ने नहीं सुनी तो आंदोलन किया। आंदोलन से बात नहीं बनी तो सरकारी कर्मचारियों को बंधक बनाया तब भी सरकार के कान पर जू नहीं रेंगा। नतीजा ग्रामीणो और पुलिस के बीच भिड़ंत हुई तीन पुलिस वाले मारे गए। जिलाधिकारी को गोली लगी। 15 किसान मरणासन्न स्थिति में अस्पताल में पड़े हैं। सरकार और जनता के बीच सीधी लड़ाई छिड़ गई हैं। महिलाएं और बच्चे गांव छोड़कर भागने लगे हैं। दो सौ रुपये देने की स्थिति में सरकार नहीं है। दो सौ करोड़ रुपये संघर्ष में खर्च करना गवारा है।

ये इक्की दुक्की घटनाएं नहीं है। जब से साहुकारों और बड़ी कंपनियों के इशारे पर किसानों की जमीनें हड़पने की

दरअसल कॉरपोरेट और सरकार की मिली भगत के कारण किसानों को सीधे पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अभी तक देश में इस बात पर कोई सहमति हीं नहीं बनी कि भूमि छीनने से पहले किसानों को पुनर्स्थापित कैसे किया जाए।

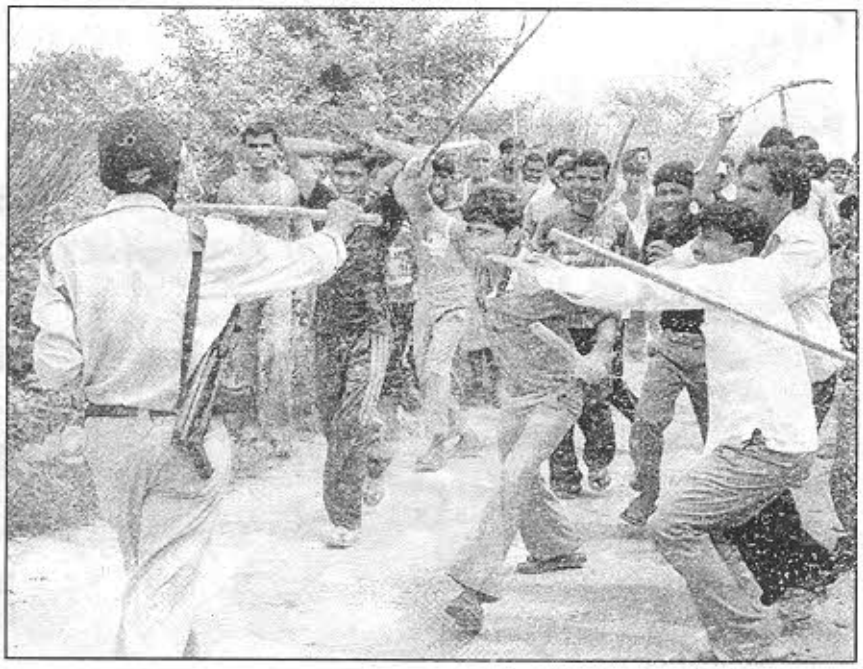

नीति बनी है तभी से ही देश भौगोलिक स्तर पर नहीं, मानसिक स्तर पर दो भागों में बंट गया है। एक के पास सब कुछ है और वह सबका अपने पास करने के लिए आतुर है। एक के पास बस कहने को थोड़ी बहुत जमीन बची है वह भी छिनी जा रही है।

स्थानीय पुलिस से लेकर मिलिटी तक उनके सामने खड़ी कर दी जा रही है। ऐसा सिर्फ नोएडा या ग्रेटर नोएडा में नहीं हो रहा है पूरे देश में हो रहा है। नोएडा से पहलं अलीगढ़ में कुछ महीनों पहले ऐसे ही संघर्ष हुआ था एक पुलिस वाले समेत चार लोगों की जान गई थी। सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। किसानों की सुनने के बजाय उत्तरप्रदेश की सरकार ताज एक्सप्रेस वे के निर्माण पर ज्यादा गंभीर है। उसके रास्ते में आने वाले हर आदमी के लिए गोली तैयार है। दो अरब डॉलर की लागत से यह छह लेन की हाईवे बन रही है। उस पर अमीर की गाडियों की रफ्तार दो सौ किलोमीटर की हो जाएगी। किसान अपनी जमीन से बाहर हो जाएंगे। किसानों की मांग है कि उनकी जमीन बाजार दर पर खरीदी जाए, सरकार कहती है कि वह अपनी दर पर खरीदेगी, दोनों दरों में 100 फीसदी की अंतर है। किसानों के अनुसार अभी जो मुआवजा मिल रहा है वह बाजार दर का आधा है।

भू–अधिग्रहण को लेकर अभी तक जो भी संघर्ष सामने आए हैं, उनसे लगभग शत प्रतिशत किसी न किसी कॉरपोरेट घराने के हित जुड़े हैं। कहीं जेपी का नाम है तो कहीं पास्को का। कहीं ट्रिडेंट है तो कहीं टाटा है। कभी वेदांता के हित सामने आते हैं तो कभी सालिम समूह के। किसी भी किसान ने समाज और सामाजिक हितों से जुड़ी परियोजनओं के लिए विरोध

भू–अधिग्रहण को लेकर अभी तक जो भी संघर्ष सामने आए हैं, उनसे लगभग शत प्रतिशत किसी न किसी कॉरपोरेट घराने के हित जुड़े हैं। कहीं जेपी का नाम है तो कहीं पास्को का। कहीं ट्रिडेंट है तो कहीं टाटा है। कभी वेदांता के हित सामने आते हैं तो कभी सालिम समूह के। किसी भी किसान ने समाज और सामाजिक हितों से जुड़ी परियोजनओं के लिए विरोध किया ही नहीं। सभी जगह की राज्य सरकारें इन कॉरपोरेट समूह के लिए कोई भी हद पार करने को तैयार है।

उड़ीसा की निलयगिरि पहाड़ियों में बॉक्साइट की खनन के लिए आई ब्रिटेन की कपंनी वेदांता ने वायदा तो किया ग्रमीणों को लाभ देने का, लेकिन किया क्या?
मायावती हो या सोनिया गांधी मौखिक रूप से सबकी प्राथमिकता किसान हैं। फिर भी किसान बर्बाद हो रहे हैं। यह कम दुखद नहीं है कि 100 करोड किसानों के रहते हुए उनके पास सिर्फ 27 फीसदी भूमि का मालिकाना हक रह गया है। शेष सभी भूमि मोटे साहुकारों या निजी कंपनियों के हाथ चली गई हैं। क्या होगा इस देश का।

किया ही नहीं। सभी जगह की राज्य सरकारें इन कॉरपोरेट समूह के लिए कोई भी हद पार करने को तैयार है।

उड़ीसा सरकार लैंको पावर परियोजना और वेदांता के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आदिवासियों को भू वचित करने के साथ साथ पर्यावरण से समझौता करने के लिए नवीन पटनायक की सरकार कुछ भी कर गुजर रही है।

पश्चिम बंगाल की कहानी किसे याद नहीं होगी। नंदी ग्राम से लेकर सिंगूर तक न जाने कितने किसानों के खून बहे।

मामला क्या था, यहीं न कि बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार इस बात पर अड़ी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए नंदी ग्राम में इंडोनेशिया के सालीम समूह और सिंगूर में टाटा को कौड़ियों के भाव जमीन देंगे ही। कहने की आवश्यता नहीं कि बंगाल की सरकार की इस जिद ने दर्जनों किसानों को मौत के मुंह में पहुंचा दिया।

पंजाब सरकार ने भी ट्रिडेंट को भूमि देने के लिए किसानों पर लाठी बरसाने में कोताही नहीं बरती। दरअसल कॉरपोरेट और सरकार की मिली भगत के कारण किसानों को सीधे पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अभी तक देश में इस बात पर कोई सहमति हीं नहीं बनी कि भूमि छीनने से पहले किसानों को पुनर्स्थापित कैसे किया जाए। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कंस्ट्रक्शन के एक पावर प्लांट के लिए वहां की सरकार ने सैकड़ों किसानों को उजाड़ दिया। जिस दिन इस कंपनी ने अपने मेगापावर प्लांट का भूमि पूजन किया उसी दिन आंध्रसरकार ने किसानों पर गोली चलाई।

उड़ीसा की निलयगिरि पहाड़ियों में बॉक्साइट की खनन के लिए आई ब्रिटेन की कपंनी वेदांता ने वायदा तो किया ग्रमीणों को लाभ देने का, लेकिन किया क्या? धीरे धीरे वहां के मूल आदिवासियों को ही वहां से भगाना शुरू कर दिया। वहां के आदिवासी न सिर्फ अपना जंगल और अपनी जमीन गंवाने लगे, बल्कि उनकी संस्कृति भी ग्रहण लग गया। बताते है कि वेदांता ने चुपके चुपके हजारों हेक्टेयर जंगल पर बुलडोजर चला दिया। यह तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने आदिवासियों और जंगल में रहने वाले लोगों की सुन ली नहीं तो निलयगिरि की पहाड़ी खोज का विषय रह जाती। अब ब्रिटिश सरकार समेत तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस लामबंदी में लगी हैं कि किसी भी तरह उनके हित सधते रहे।

इतने ज्वलंत विषय होने बाद भी यह मुद्दा राजनीतिक समर्थन और विरोध का बन कर रह गया है। संसद में इस पर खूब हंगामे हो चुके है। सत्ता पक्ष भी किसानों पर हो रहे जुल्मों को लेकर घड़ियाली आसूं बहाते रहे हैं। मायावती हो या सोनिया गांधी मौखिक रूप से सबकी प्राथमिकता किसान हैं। फिर भी किसान बर्बाद हो रहे हैं। यह कम दुखद नहीं है कि 100 करोड किसानों के रहते हुए उनके पास सिर्फ 27 फीसदी भूमि का मालिकाना हक रह गया है। शेष सभी भूमि मोटे साहुकारों या निजी कंपनियों के हाथ चली गई हैं। क्या होगा इस देश का। ❑